**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding the issue of redevelopment under the scheme 'Housing For All'.

**श्री मनोज कोटक (मुंबई उत्तर-पूर्व):** धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2022 तक 'हाउजिंग फॉर ऑल' योजना के माध्यम से सभी को घर देने की बात कही है । मैं मुंबई शहर से आता हूं । यहां पर आधे से ज्यादा आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है और झुग्गी बस्तियों की ओनरशिप कहीं पर राज्य सरकार की है, कहीं पर महानगर पालिका की है और कहीं पर प्राइवेट लैंड वालों की है । उसके साथ-साथ केंद्र सरकार की जमीनें भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं, जिसमें एयरपोर्ट लैंड है, रेलवे की जगह है, बीपीटी की लैंड है । इसके साथ-साथ कुछ पीएसयू की जमीन पर भी झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं । हमारा सपना 'हाउजिंग फॉर ऑल' योजना के माध्यम से सभी के लिए घरों की व्यवस्था करना है । इन जमीनों पर जो झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं, वहां पिछले 50 सालों में उनके पुनर्वास की कोई पॉलिसी नहीं बनी है । केंद्र सरकार की जिन जमीनों पर झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं, उनको हम अलग-अलग तरीकों से प्राथमिक सुविधाएं तो प्रदान करते हैं, लेकिन उनको अच्छे घर और सही मकान देने की कोई पॉलिसी न होने के कारण मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके लिए घरों की व्यवस्था की जाए, इनको रीडेवलपमेंट का चांस मिले और ये रीडेवलपमेंट से अच्छा घर पा सकें । इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र नेवल विभाग के आसपास की जमीनों पर भी बहुत सारे पुराने मकान और झुग्गी बस्तियां हैं, जिनकी एनओसी के बिना प्रश्न अटका हुआ है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार की जमीनों और संस्थानों की एनओसी के कारण जो रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, उसके कारण जिनको घर नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए ।